

राजस्थान मंडपम् व यूनिटी मॉल के खिलाफ दायर पी.आई.एल. सुप्रीम कोर्ट में खारिज

शीर्ष अदालत ने कहा कि, “जयपुर की यह विवादित भूमि, वन भूमि नहीं है और आवेदन में कोई औचित्य नहीं पाया गया है”

–कार्यालय संवाददाता–
जयपुर । सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर में राज्य सरकार की दो योजनाओं राजस्थान मंडपम् व यूनिटी मॉल का निर्माण रोकने और इस जमीन को वन भूमि घोषित करने के लिए दायर पीआईएल को खारिज कर दिया। सीजेआई बी.आर.गवई व जस्टिस के. विनोद चन्द्रन ने यह आदेश टी.एन. गोदावर्मन मामले में दायर एक पीआईएल पर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित भूमि वन भूमि नहीं है और आवेदन में कोई औचित्य नहीं पाया गया है। याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि जयपुर की सांगानेर तहसील स्थित डोल का बाड़ क्षेत्र में इन परियोजना की जमीन वन भूमि है, और

- ज्ञात रहे कि यूनिटी मॉल, जो प्रधानमंत्री की वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट पहल का हिस्सा है, तथा राजस्थान मंडपम्, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, आईटी टॉवर, फाइव स्टार और फोर स्टार होटल्स तथा रिहायशी टावर्स - ये सभी परियोजनाएं राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 95 एकड़ रीको भूमि पर अनुमोदित की गई हैं।

ऐसे में इसे वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत संरक्षण दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही यहां पर इन परियोजनाओं के निर्माण पर पाबंदी लगाई जाए।

जवाब में राज्य सरकार व रीको की ओर से एएजी शिवमंगल शर्मा ने कहा कि संबंधित भूमि 1979 में औद्योगिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहित की गई थी। इसकी वैधता

छिपाने पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। राज्य सरकार ने परियोजना वाली जगह पर कोई पेड़ नहीं काटे हैं और केवल 56 पेड़ों को ही मंजूरी लेकर प्रत्यारोपित किया है। वहीं उनकी संख्या से 10 गुना अधिक पौधे वृक्षारोपण के तौर पर लगाए हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया है। ज्ञात रहे कि यूनिटी मॉल, जो प्रधानमंत्री की वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट पहल का हिस्सा है, तथा राजस्थान मंडपम्, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, आईटी टॉवर, फाइव स्टार और फोर स्टार होटल्स तथा रिहायशी टावर्स – ये सभी परियोजनाएं राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 95 एकड़ रीको भूमि पर अनुमोदित की गई हैं।

एफएमडी नेटवर्क लेबोरेट्री की समीक्षा बैठक

जयपुर। देश में पशुधन स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा खुरपका मुहपका रोग (एफएमडी) नियंत्रण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा के लिए एफएमडी नेटवर्क लेबोरेट्री की 3२वीं वार्षिक समीक्षा बैठक का दो दिवसीय आयोजन आज जयपुर में राज्य रोग निदान केंद्र, पशुपालन विभाग के तत्वावधान में संपन्न हुआ। संयुक्त निदेशक राज्य रोग निदान केंद्र डॉ. लोकेश कुमार शर्मा ने बताया कि ।

प्रसारण निगम का नया पेंशन पोर्टल शुरू

जयपुर। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम ने पेंशनधारी कर्मचारियों के लिए एक नया ऑनलाइन पेंशन पोर्टल शुरू किया है। अब पेंशन से जुड़ी जानकारी या दस्तावेजों के लिए कर्मचारियों को अब दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगे, व घर बैठे ही पेंशन सम्बन्धी सेवायें ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे।प्रसारण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से पेंशनधारी कर्मचारी जीवित प्रमाण पत्र, पेंशन से जुड़ी रिपोर्ट, आदेश और भुगतान की जानकारी आसानी से ऑनलाइन देख व डाउनलोड कर सकेंगे।

एस.एम.एस. अस्पताल में रिश्वतकांड के बाद तीन पुराने कर्मचारी हटाए

- कार्यालय संवाददाता–
जयपुर । रिश्वत कांड में पकड़े गए सर्वाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के डॉ मनीष अग्रवाल के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने स्टोर शाखा में फेरबदल किया है।

जिसमें प्रिंसिपल ने स्टोर शाखा के तीन कर्मचारियों को वहां से हटा कर उनकी जगह नए कर्मचारियों को नियुक्त किया है। इसके अलावा जो कर्मचारी सालों से स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत था, उसे हटाकर स्टोर इंचार्ज बना दिया गया है। कॉलेज के आदेशों के अनुसार, स्टोर शाखा (उपापन) में कार्यरत जगदीश प्रसाद यादव को हटाकर स्टोर कीपर बनाया गया है।

वहीं केदार प्रसाद स्वर्णकार (सामान्य शाखा) और ऋषि कुमार (संस्थापन शाखा) को स्टोर शाखा (उपापन) में नियुक्त किया गया है। सुरेन्द्र कुमार पाटीदार को स्टोर शाखा (उपापन) से सामान्य शाखा में, प्रमोद सिंह को लेखा शाखा से भंडार शाखा में और धनंजय सिंह को भंडार शाखा से लेखा शाखा में स्थानांतरित किया गया है।

- स्टोर कीपर को हटाकर स्टोर इंचार्ज का सौंपी जिम्मेदारी

इसके अलावा, शंकर लाल जलुथरिया, जो पिछले कई सालों से स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत थे, शंकर लाल जलुथरिया को अब स्टोर इंचार्ज बनाया गया है। बताया जा रहा है कि रिश्वत कांड में पकड़े गए डॉ मनीष अग्रवाल पर 1१ शाखाओं का भार था , वो 1१ शाखाओं का काम देखते थे। डॉ मनीष अग्रवाल के पास आईटी सेल, आरटीआई एवं लीगल सेल, महिला एवं जनाना हॉस्पिटल के सुपरविजन, पैरा क्लिनिक डिपार्टमेंट समेत कई अन्य विभागों का प्रभार था।बताया जा रहा है।

कि मेडिकल कॉलेज में स्टोर शाखा का महत्वपूर्ण रोल है। मेडिकल कॉलेज के अलावा इससे अटैच 7 अन्य अस्पताल में मेडिकल से जुड़े उपकरण तमाम सामान और दवाईयां सप्लाई होती है।

पंचायतीराज विभाग का अधिशाषी अभियंता रामवतार मीणा निकला करोड़ों का मालिक ए.सी.बी. की टीमों ने ऑपरेशन “भूदेव” चलाकर रामवतार मीणा के जयपुर, करौली, गंगापुर सिटी और उदयपुर में एक दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया

–कार्यालय संवाददाता–
जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ए.सी.बी.) ने कार्रवाई करते हुए पंचायती राज विभाग इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर के अधिशाषी अभियंता हाल एसोसियेट प्रोफेसर रामावतार मीणा के विरूद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दंड कर ऑपरेशन “भूदेव” चलाया। ए.सी.बी. ने रामवतार के जयपुर, करौली, गंगापुर सिटी व उदयपुर में स्थित एक दर्जन ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया। एसीबी की सर्च कार्यवाही में करोड़ों रुपये के आलीशान मकान और फार्म हाउस होने की पुष्टि हुई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सिमता श्रीवास्तव ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय को गोपनीय शिकायत प्राप्त हुई थी कि पंचायती राज विभाग,इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर के अधिशाषी अभियंता हाल एसोसियेट प्रोफेसर रामावतार मीणा द्वारा पद पर रहते हुए रिश्वत प्राप्त की जाकर भ्रष्ट तरीके से भ्रष्टाचार के द्वारा स्वयं एवं अपने परिवारजनों के नाम से अपनी वैध आय से अनुपातिक रूप से अधिक चल-अचल सम्पत्तियां



आरोपी रामवतार मीणा

अर्जित की गई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करोड़ों रूपै है। इस शिकायत का एसीबी की इंटेलिजेंस टीम ने गोपनीय रूप से सत्यापन किया गया तथा अधिकारी द्वारा जयपुर, गंगापुर सिटी, करौली, उदयपुर के विभिन्न स्थानों पर आवासीय भूखण्ड, प्लॉट्स, फार्म हाउस, कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, अर्जित करने के तथ्य प्रकट हुए। जिस पर विस्तृत रूप से तथ्य संकलित किये गये एवं तथ्यों की जाकर भ्रष्ट तरीके से भ्रष्टाचार के द्वारा स्वयं एवं अपने परिवारजनों के नाम से अपनी वैध आय से अनुपातिक रूप से अधिक चल-अचल सम्पत्तियां

‘कागजों में नहीं धरातल पर काम चाहिए, स्कूलों की मरम्मत का निरीक्षण स्वतंत्र बांडी से भी हो’

- कार्यालय संवाददाता–
जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की जर्जर स्कूलों को लेकर कहा है कि उन्हें कागजों में काम नहीं चाहिए, बल्कि काम धरातल पर दिखना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने स्कूलों में कराए जा रहे रिपेयरिंग के काम का निरीक्षण स्वतंत्र बांडी से कराने की मंशा जताते हुए न्यायमित्र सहित सभी पक्षों को इसके लिए नाम सुझाने को कहा है। वहीं अदालत ने 31 अक्टूबर तक राज्य सरकार को प्रकरण में विद्यार्थियों की मौत के बाद प्रकरण में लिए स्वप्रेरित प्रसंगान पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने शपथ पत्र के जरिए

- राजस्थान में जर्जर स्कूलों के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक राज्य सरकार को विस्तृत कार्य योजना पेश करने के आदेश दिए
- अदालत ने यह आदेश झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिरने से विद्यार्थियों की मौत के बाद प्रकरण में लिए स्वप्रेरित प्रसंगान पर सुनवाई करते हुए दिए

जर्जर स्कूलों की मरम्मत को लेकर अदालत में जानकारी दी। महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि अधिक जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए पांच लाख रुपए का बजट तय किया गया है और आगामी मार्च माह तक काम पूरा कर लिया जाएगा। वहीं शेष स्कूलों में मरम्मत का काम नवंबर, 2026 तक पूरा कर लेंगे। अदालत से कहा कि 5 लाख रुपए में मरम्मत कैसे होगी, लाखों रुपए तो रंग-सफेदी में ही लग जाते हैं। ऐसा लगता

है कि बिना परीक्षण किए सतही तौर पर यह राशि तय की गई है। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि जरूरत पड़ेगी तो और बजट जारी किया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों के लिए कुल बजट का 1१.46 फीसदी बजट स्वीकृत किया गया है। अदालत ने मरम्मत के काम के निरीक्षण का काम स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मंशा जताते हुए कहा कि ठेकेदार की गलती से घटनाएं होती हैं। ऐसे में पीडब्ल्यूडी से निरीक्षण कराने के बजाए

दिवाली से पूर्व 1५9 आवंटियों को मिले सपनों के घर के आवंटन पत्र

यू.डी.एच. मंत्री झाबर सिंह खर्ा ने लाभार्थियों को सौंपे दस्तावेज

जयपुर। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित समृद्धि अपार्टमेंट, जयपुर के 159 पात्र आवंटियों को बुधवार को उनके आवंटन पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्ा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उन्होंने लाभार्थियों को उनके सपनों के घर के दस्तावेज सौंपे ।

यह आयोजन प्रताप नगर स्थित

- शहरी सेवा शिविर 2025 में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने अब तक 2200 से ज्यादा प्रकरणों को निस्तारण किया

मण्डल के वृत्त प्रथम कार्यालय में चल रहे शहरी सेवा शिविर 2025 अभियान के अंतर्गत किया गया। मंत्री खर्ा ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल मकान बनाना नहीं, बल्कि हर परिवार को सम्मानजनक जीवन देना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में हर सर को छत के संकल्प को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री खर्ा ने सभी 159 आवंटियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह घर केवल चार दीवारें नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत और आत्मनिर्भर जीवन की नींव

आयकर विभाग जयपुर रेंज प्रथम का एमटीएस गिरफ्तार

जयपुर (कासं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय की जयपुर नगर तृतीय जयपुर टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए आयकर विभाग जयपुर रेंज-प्रथम एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) के विष्णु पारीक को दस हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सिमता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी चौकी जयपुर नगर तृतीय जयपुर को परिव्रादी ने शिकायत दी कि उसकी फर्म साकेत जेम्स के आयकर रिटर्न वर्ष 2014-15 के आयकर अपीलीय



अधिकरण न्यायपीठ जयपुर द्वारा दिये गये फैसले में परिव्रादी के करीब 58 लाख रुपये आयकर विभाग को लौटाने का आदेश जून 2024 में दिये।

“विकसित राजस्थान 2०47” के विजन डॉक्यूमेंट पर काम कर रही भजनलाल सरकार

- वर्ष 2047 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य
- जयपुर (कासं)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के “विकसित भारत 2047” के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी “विकसित राजस्थान 2047” विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इसमें प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भजनलाल सरकार गरीब, युवा, महिला और किसानों के सशक्तीकरण को केन्द्र में रखते हुए इस विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक काम कर ही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बने इस विजन डॉक्यूमेंट में राजस्थान में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में विकास के लिए लक्ष्य तय किये गए हैं। इनके अनुरूप प्रदेश में शत-प्रतिशत साक्षरता, कौशल आधारित शिक्षा, सुलभ एवं आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, जलवायु अनुकूल-जल प्रबंधन, स्मार्ट शहरीकरण और कृषिफायती राज्य सुनिश्चित किए जाएंगे। साथ ही, महिलाओं और युवाओं को कौशल, उद्यमिता एवं लक्ष्य के अवसर प्रदान कर उनकी राज्य के विकास यात्रा में भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

यह विजन चार प्रमुख थीम और 1३ सेक्टर पर आधारित है। पहली थीम जनकल्याण और सामाजिक सशक्तीकरण है, जिसमें कृषि-खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समावेशन जैसे आयाम शामिल हैं। दूसरी थीम त्वरित विकास, समृद्धि और रोजगार सृजन पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत औद्योगिक, खनन और पर्यटन क्षेत्रों में नई संभावनाएं विकसित की जा रही हैं। तीसरी थीम भविष्य उन्मुख राजस्थान की है, जिसमें आधारभूत अवसंरचना, जल सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थायित्व और जलवायु अनुकूलता को प्राथमिकता दी गई है। चौथी थीम संवर्धक नीति, वित्त और शासन की है, जो ग्रामीण व शहरी विकास, प्रभावी शासन, डिजिटल सेवाओं और वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने पर केंद्रित है। राज्य सरकार ने वर्ष 2०47 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

स्वतंत्र एजेंसी से कराया जाना चाहिए अदालत ने महाधिवक्ता को कहा कि आप काम करने की बात कह रहे हैं, लेकिन धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज भी टीन शेड के नीचे स्कूल संचालित हो रही हैं। सभी जिलों की स्कूलों की ग्रैंडिंग तय हो ताकि, काम को लेकर प्राथमिकता तय हो सके। इस पर अदालत ने कहा कि फिलहाल फोकस सुरक्षा को लेकर है। अदालत मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। वहीं स्वतंत्र संस्था से रिपेयरिंग का निरीक्षण स्वतंत्र एजेंसी से कराने के संबंध में सरकार से निर्देश लेने पड़ेगे। एजी ने कहा कि नवंबर माह में केन्द्र सरकार से भी पैसा जारी होगा और उन्हें रोडमैप पेश करने के लिए समय दिया जाए। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर को तय करते हुए सभी पक्षों को स्वतंत्र एजेंसी का नाम सुझाने को कहा है।

एक अप्रैल से नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू करने पर मंथन

जयपुर । बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध कराने और पढ़ाई के दिवसों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग आगामी सत्र से एक बड़ा नवाचार करने की ओर अग्रसर है। इसके तहत विभाग अगला शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से आरंभ करने पर विचार कर रहा है। इस बाबत शिक्षा संकुल में शासन सचिव, स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल के अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभाग के पदाधिकारियों एवं शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से नए सत्र को एक अप्रैल से शुरू करने पर मंथन किया गया। बैठक में शासन सचिव कुणाल ने इस नवाचार के उद्देश्य बताते हुए कहा कि शैक्षिक सत्र में परिवर्तन से एनईपी 2020 के अनुरूप शिक्षण संभव होगा। इससे न केवल शिक्षण दिवसों की संख्या 180 से बढ़कर 210-220 दिवस तक हो जाएगी, बल्कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अधिक समय भी मिलेगा। इसके साथ ही सीबीएसई के शैक्षणिक कैलेंडर से एकरूपता स्थापित होने से विद्यालयों में नामांकन दर में वृद्धि की भी संभावना है।

इस दौरान उन्होंने शिक्षकों की कथित समस्याओं की भी ध्यान पूर्वक सुना और उनके जल्द समाधान का आश्वासन दिया। बैठक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा सतीश्वर जाट ने उपस्थित प्रतिनिधियों से आवश्यक सुझाव आमंत्रित किए और विभाग की ओर से सभी आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया।